शिक्षक उस नरेन्द्र से इस नरेन्द्र के सपने को साकार करने में भूमिका निभायें- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने राजस्थान शिक्षक संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया

बांसवाड़ा, 20 दिसम्बर (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षकों का आव्हान किया कि वे नई शिक्षा नीति के अनुरूप तार्किक सोच रखें और भारत को आगे बढ़ाने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि देश निर्णायक मोड़ पर है, ऐसे में उस नरेन्द्र से इस नरेन्द्र के 21वीं सद्दी के सपने को पूरा करने के लिए शिक्षक अपनी महती भूमिका अदा करें। शर्मा राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा।

प्रदेश स्तरीय सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्य अतिथि पद से उपस्थितजनों को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञान सिर्फ अक्षर और पुस्तक तक नहीं सिमटना चाहिए, वरन् संस्कार, विचार और आत्मीयता के उच्च मूल्य तक पहुॅंचना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि अब तक जितने भी परिवर्तन हुए हैं, उनका नेतृत्व शिक्षकों ने किया है। चाणक्य ने कहा था कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं।

मुख्यमंत्री ने वागड़ के सभी देवी देवताओं का जयकारा लगाते हुए सभी शिक्षकों को नमन एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि मैं आशीर्वाद देने नहीं, वरन् आप सभी गुरुजनों से आशीर्वाद लेने आया हूं। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पियेगा, वह दहाड़ेगा।

उन्होंने कहा कि गरीब व वंचितों को मुख्य धारा में लाना शिक्षा से ही संभव है। बेणेश्वर धाम महंत अच्युतानंद महाराज ने मुख्यमंत्री व शिक्षकों को आगामी 3 जनवरी पौष पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम में आयोजित होने वाली विशाल पदयात्रा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी, हेमंत मीणा एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, महेन्द्र कपूर मौजूद थे। मुख्य वक्ता प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ नारायण लाल गुप्ता थे।

205 दवाओं के सैंपल फेल

नई दिल्ली, 20 दिसंबर। हाल ही में देश में दवाओं के सैंपल्स की गुणवत्ता जांच में 205 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं।

केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने देशभर में बनी दवाओं के सैंपल लिए थे, जिनमें खांसी, बुखार, शुगर और हार्ट अटैक से जुड़ी दवाएं शामिल थीं।

इन दवाओं में से 47 हिमाचल प्रदेश में बनाई गई थीं। हिमाचल में

■ इन दवाओं में हार्ट अटैक, बुखार-खाँसी की मैडिसिन भी शामिल हैं और अधिकांश दवाएं हिमाचल प्रदेश की कंपनियों में बनी हैं।

जिन जिलों की कंपनियों की दवाएं फेल हुई हैं, उनमें सोलन जिले की 28, सिरमौर की 18 और ऊना की एक कंपनी शामिल है। सभी संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

फेल दवाओं में पैरासिटामोल, मेटफॉर्मिन, एस्पिरिन, रेमिप्रिल, क्लोपिडोग्रेल, सोडियम वैल्प्रोएट, मेबेवेरिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लेरिथ्रोमाइसिन, टेलमीसार्टन, सेफिसाइन और जेंटामाइसिन इंजेक्शन जैसी दवाएं शामिल हैं, जो टाइफाइड, फेफड़ों व मूत्र संक्रमण, अस्थमा, खांसी, एलर्जी और पाचन तंत्र की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं।

वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में डमी बैठाने वाले दो जालसाज़ गिरफ्तार

जयपुर, 20 दिसम्बर। एसओजी (स्पैशल ऑपरेशन ग्रुप) ने वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) भर्ती परीक्षा 2022 में डमी परीक्षार्थी बिठाकर फर्जी तरीके से चयनित होने वाले दो मुख्य आरोपियों, दिनेश कुमार और दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि ये दोनों आरोपी पिछले दो वर्षों से पुलिस को चकमा दे रहे थे। इनके खिलाफ न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था और एसओजी ने इन पर पांच-पांच

■ दो साल से पुलिस को चकमा दे रहे दोनों आरोपियों को एसओजी ने पुणे व जयपुर में पकड़ा।

हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था।

मामला वर्ष 2022 की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने 29 जनवरी 2023 को सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान विषय की परीक्षाओं में खुद बैठने के बजाय डमी परीक्षार्थियों को बिठाया था और ये दोनों वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान विषय) के पद पर चयनित भी हो गए थे। लेकिन जांच की आंच पहुंचते ही फरार हो गए।

पुलिस उपमहानिरीक्षक परिस देशमुख के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने आरोपी दिनेश कुमार को महाराष्ट्र के पुणे से और आरोपी दिनेश कुमार को जयपुर से गिरफ्तार किया।

एसओजी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार शर्मा मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। अब पुलिस का मुख्य फोकस उन डमी परीक्षार्थियों तक पहुँचना है, जो इन आरोपियों की जगह परीक्षा में बैठे थे।

जस्टिस स्वामीनाथन पर महाभियोग की कोशिश पर 36 पूर्व जज भड़के

नई दिल्ली, 20 दिसंबर। मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जी. आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग लाने की विपक्षी दलों कोशिश पर देश के 36 पूर्व न्यायाधीशों ने कड़ी आपत्ति जताई है। पूर्व जजों ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की जड़ों पर सीधा हमला बताते हुए संसद सदस्यों और आम जनता से इस कदम की खुलकर निंदा करने की अपील की है।

पूर्व न्यायाधीशों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि अगर इस तरह की कोशिशों को आगे बढ़ने दिया गया, तो इससे न्यायाधीशों को राजनीतिक और वैचारिक दबाव में काम करने के लिए

■ उन्होंने कहा, न्यायपालिका और लोकतंत्र को भारी खतरा है

मजबूर किया जाएगा, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

बयान में यह भी कहा गया कि यह कोई अकेली घटना नहीं है। पूर्व जजों ने 2018 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग की कोशिश और बाद में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई, एस. ए. बोबडे और डी. वाई. चंद्रचूड़ के खिलाफ चलाए गए अभियानों का भी जिक्र किया। उन्होंने मौजूदा सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ हो रहे हमलों को भी इसी खतरनाक प्रवृत्ति का हिस्सा बताया।

ज्ञातव्य है कि 1 दिसंबर को जस्टिस स्वामीनाथन ने आदेश दिया था कि तमिलनाडु के अरुलमिघु सुब्रमणिया स्वामी मंदिर में दीपथून ? के दौरान दीप जलाना मंदिर की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इससे पास स्थित दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। इस फैसले के बाद विवाद खड़ा हो गया।

भाजपा का पलटवार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर "भूत" लाभार्थियों (अर्थात् जो हैं ही नहीं) के नाम थे, और इसके जरिए गरीबों तक पहुँचने वाले हर एक रूपए पर 5 रूपए खर्च होते हैं।

सरकार के 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, 193.67 करोड़ की दस्तावेजी हेराफेरी पाई गई है। 23 राज्यों में निगरानी से यह पाया गया कि या तो काम "नहीं मिले, या खर्च के अनुपात में नहीं थे।" इस बीच, 12,219 करोड़ रूपए की मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, यह वह धन है जो श्रमिकों को देना है, लेकिन एक ऐसे सिस्टम में फंसा हुआ है, जो समय पर भुगतान की गारंटी नहीं दे सकता।

अब देखें कि वीबी जी राम जी बिल वास्तव में क्या निर्धारित करता है: प्रत्येक लेन-देन के लिए बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण, कार्य स्थलों पर जीपीएस और सैटेलाइट निगरानी, धोखाधड़ी की ए आई से पहचान, और प्रति सप्ताह जानकारी सार्वजनिक करना। विपक्ष इसे "निगरानी" कहता है। एक अधिक सटीक विवरण यह है कि इससे भूतिया श्रमिकों को बनाए रखना और काल्पनिक कार्य स्थलों का दावा करना तथा गबन छिपाना कठिन हो जाता है।

60:40 फंडिंग विभाजन पूरी गणना को बदल देता है। जब राज्य को 40 प्रतिशत लागत वहन करनी होगी तो उनकी नौकरशाही के पास अचानक यह कारण आ जाएगा कि है कि खर्च वास्तविक हो। ग्राम पंचायतों को, जो राजनीतिक समर्थकों को काम सौंपती थीं, अब बिचौलियों का बायोमीट्रिक सत्यापन का सामना करना होगा, जो हर लेन-देन से अपना हिस्सा निकालते थे, अब वास्तविक समय में जीपीएस ट्रैकिंग का सामना करना होगा।

इसलिए, इस बहस का फोकस "संघवाद" और "अधिकारों" पर है, न कि कार्यान्वयन पर। वास्तविक स्थिति प्रतिकूल है। भारत की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) संरचना पहले ही यह साबित कर चुकी है कि क्या संभव है, 2009 से अब तक 3.48 लाख करोड़ की कुल बचत हुई, जिसमें 9.2 करोड़ फर्जी या डुप्लिकेट लाभार्थियों को सरकारी रजिस्टर से हटा दिया गया। कल्याण दक्षता सूचकांक 2014 में 0.32 था, जो 2023 में बढ़कर 0.91 हो गया।

विपक्ष मानता है कि मनरेगा के वर्तमान रूप में लागू होने की रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन केवल 7.61 प्रतिशत पंजीकृत परिवार ही 100 कार्य दिवस पूरा करते हैं। औसतन यह 50-60 दिनों के आसपास रहता है। कानूनी रूप से गारंटीकृत अधिकार, अधिकांश प्रतिभागियों के लिए, एक सैद्धांतिक अवधारणा है, जबकि प्रशासनिक लागत और रिसाव वास्तविक आर्थिक लागत पर असर डालते हैं।

वीबी जी राम जी बिल का मुख्य लॉजिक सटीक है: जवाबदेही तंत्र असली श्रमिकों के लिए संसाधन खोल देता हैं और फर्जी श्रमिकों को समाप्त करता है। सवाल यह नहीं है कि मनरेगा में बदलाव होना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि विपक्ष का असली विरोध सुधार से है, या उस नियंत्रण खोने से, जो सुधार के कारण खतरे में आ गया है।

दिल्ली में आज फिर 138 उड़ानें रद्द

नयी दिल्ली, 20 दिसंबर। दिल्ली-एनसीआर सहित, उत्तर तथा पूर्वी भारत के कई हिस्सों में कोहरे के कारण यहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को 138 उड़ानें रद्द रहीं। दिल्ली हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि

■ दिल्ली सहित उत्तर भारत में भारी कोहरे का प्रकोप बना हुआ है।

आज दिल्ली से जाने वाली 69 और दूसरे शहरों से यहां आने वाली इतनी ही उड़ानें रद्द रहीं। इसके अलावा कुछ उड़ानों में देरी की भी सूचना है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली समेत उत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में इन दिनों तड़के और सुबह के समय घना कोहरा बन रहा है, जिससे उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि रविवार को भी हवाई अड्डे पर घना कोहरा रहेगा और तड़के दृश्यता 100 मीटर तक गिर सकती है।

राजधानी एक्सप्रैस हाथियों के झुंड से टकराई, सात हाथियों की मौत

दुर्घटना में ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए, कोई यात्री घायल नहीं हुआ

गुवाहाटी, 20 दिसंबर। असम के नागांव जिले में नयी दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस शुक्रवार देर रात एक हाथियों के झुंड से टकरा गयी, जिससे ट्रेन के पांच डिब्बे पटरी से उतर गये और सात हाथियों की मौत हो गयी। इस दुर्घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ।

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह घटना कल देर रात करीब दो बजे हुई, जब सैरांग (मिजोरम) से नयी दिल्ली जा रही ट्रेन जमुनामुख-कम्पुर सेक्शन के अंतर्गत हाथियों के झुंड से टकरा गयी। यह क्षेत्र हाथियों के लिए चिह्नित क्षेत्र नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों ने हाल के दिनों में वहां हाथियों को विचरण करते हुए देखा था।

■ पूर्वोतर सीमान्त रेल्वे के अधिकारियों ने बताया कि हादसा जिस क्षेत्र में हुआ वह हाथियों के लिए चिन्हित नहीं है, पर हाल ही में वहां हाथियों की सक्रियता देखी गई है।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि की है। एनएफआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना लुमडिंग डिवीजन के जमुनामुख-कम्पुर सेक्शन में हुई, जहां ट्रेन संख्या 20507 डीएन सैरांग-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हाथियों झुंड से टकरा गयी, जिसके कारण लोकोमोटिव और पांच डिब्बे पटरी से उतर गये। किसी यात्री को इस दुर्घटना से कोई चोट या हानि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि घटना स्थल गुवाहाटी से लगभग 126 किमी दूर है। दुर्घटना राहत ट्रेनें और डिवीजनल मुख्यालय के अधिकारी मौके पर पहुंच गये हैं। पटरी से उतरे डिब्बों के यात्रियों को अस्थायी तौर पर अन्य डिब्बों में खाली बर्थ में पर भेजा गया है। डिब्बों को अलग करने के बाद ट्रेन सुबह 6:11 बजे गुवाहाटी के लिए रवाना हो गयी। शर्मा ने कहा कि यह घटना ऐसे स्थान पर हुई जो हाथियों के लिए निर्धारित गलियारा नहीं है। लोको पायलट ने हाथियों के झुंड को देखकर आपात स्थिति में ब्रेक लगाये, लेकिन फिर भी हाथी ट्रेन की चपेट में आ गये। इस सेक्शन से गुजरने वाली अन्य ट्रेनों को अप लाइन के माध्यम से डायवर्ट किया जा रहा है और पटरी की मरम्मत का कार्य जारी है।

अमित शाह का हिमाचल दौरा रद्द

कांगड़ा, 20 दिसंबर। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल प्रदेश का प्रस्तावित दौरा रद्द हो गया है। गृह मंत्री को आज ज्वालामुखी स्थित सपड़ी में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के

■ शाह सशस्त्र सीमाबल के 62 वें स्थापना दिवस में शामिल होने वाले थे।

62वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होना था, लेकिन ऐन मौके पर उनका दौरा रद्द हो गया। एसएसबी सपड़ी प्रशासन ने इस बाबत आधिकारिक जानकारी सांझा की है। हालांकि गृह मंत्री का दौरा किन कारणों के चलते रद्द हुआ इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी गई है।

अमित शाह के दौरे के रद्द होने के बाद अब कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

भाजपा के मंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

व्यवहार के उदाहरण हैं, जिनकी उम्मीद राहुल गांधी से नहीं की जाती, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत में उनमें धैर्य का नितांत अभाव दिखता है।

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ प्रियंका गांधी की बातचीत भी वायरल हुई और मीडिया ने उनकी तस्वीरें हर जगह दिखाईं।

यहाँ तक कि भाजपा के मंत्री और सांसद भी आपस में प्रियंका गांधी की चर्चा करते सुने गए और यह कहते दिखे कि उनका व्यवहार राहुल गांधी से कितना अलग था और उनका प्रदर्शन कितना असरदार रहा।

जितनी चर्चा और सराहना प्रियंका गांधी को मिली, उसे देखते हुए लगता है कि राहुल गांधी को अपनी जर्मनी यात्रा का समय बेहतर ढंग से तय करना चाहिए था और संभव है कि उन्हें और उनकी टीम को संसद से उनकी गैरमौजूदगी के समय पर अफ़सोस भी हो रहा हो।

वो दिन गए, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का समर्थन किया। पिछले 18 महीनों से भाजपा पार्टी अध्यक्ष के लिए किसी नाम पर फ़ैसला नहीं कर पा रही थी। यह कोई संयोग नहीं है कि बिहार की जीत के तुरंत बाद अपेक्षाकृत कम चर्चित नेता नितिन नबीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। सभी संकेत यही बताते हैं कि निकट भविष्य में तथा सम्भवत: और आगे भी नबीन हर तरह से मोदी-शाह की इस जोड़ी के अधीन रहकर ही काम करेंगे। बीते महीनों की रिपोर्ट बताती थीं कि आरएसएस भाजपा अध्यक्ष पद पर अपने पसंदीदा व्यक्ति को बैठाने के लिए दृढ़ था। नबीन की नियुक्ति से भले ही पीढ़ीगत बदलाव का संकेत मिलता हो, लेकिन इसे आरएसएस की जीत के रूप में नहीं देखा जा रहा है।

राजस्थान में नये ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हालांकि वकीलों ने हाईकोर्ट के इस नए कैलेंडर का विरोध किया है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा सहित, अन्य वकीलों और संगठनों ने इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर इस पर पुनर्विचार करने का निवेदन किया है।

रविवार को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा भी उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में लगभग 19 लाख 45 हजार महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गई हैं।

हथियार तस्करी का आरोपी भगोड़ा सैनिक गिरफ्तार

मोहाली, 20 दिसंबर। पंजाब में मोहाली के स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल (एसएसओसी) ने सेना के भगोड़े राजबीर सिंह उर्फ फौजी और उसके साथी को सीमा पार ड्रग्स और हथियारों की तस्करी रैकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने शनिवार को बताया कि सभी लिंक पर तेजी से कार्रवाई करते हुए, ऑपरेशन ने टेरर फाइनेंसिंग और ड्रग तस्करी में शामिल एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जिससे एक हैंड ग्रेनेड और 500 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। उन्होंने कहा कि राजबीर सिंह इस साल की शुरुआत में पुलिस थाना घरिंडा, अमृतसर ग्रामीण में दर्ज एक जासूसी मामले में भी वांछित है। यादव ने कहा कि जांच में हरियाणा के सिरसा में एक महिला पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमले की साजिश में उसकी भूमिका का भी पता चला है, जिसमें हैंड ग्रेनेड की डिलीवरी और हमले के लिए फंडिंग शामिल है। इस मामले की जांच जारी है।

सोनिया गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कार्यसमिति (सी.डब्ल्यु.सी.) की एक पूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में प्रस्तावित संशोधनों के ख़िलाफ़ देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी।

कांग्रेस का आरोप है कि केन्द्र सरकार द्वारा क़रीब 40 प्रतिशत वित्तीय बोझ राज्यों पर डालने की योजना, दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक, मनरेगा को प्रभावी ढंग से खोखला कर देगी।

कांग्रेस नेताओं के अनुसार, कई राज्य, जो पहले ही गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, केन्द्र को बता चुके हैं कि सुनिश्चित केन्द्रीय फण्डिंग के बिना वे इस योजना को लागू करने की स्थिति में नहीं हैं। एक वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी ने कहा, "यह और कुछ नहीं, बल्कि केन्द्र की ज़िम्मेदारी राज्यों पर थोपने की कोशिश है, जबकि कई राज्य मुश्किल से वेतन और ज़रूरी कल्याण योजनाएँ चला पा रहे हैं।"

यूपीए दौर में मनरेगा की मुख्य शिल्पकार मानी जाने वाली सोनिया गांधी ने इस मुद्दे की व्यक्तिगत कमान संभाल ली है। संसद की अग्रिम पंक्तियों से लेकर सदन के बाहर सार्वजनिक संदेशों तक, उन्होंने लगातार चेतावनी दी है कि ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना की संरचना में बदलाव सबसे ग़रीब नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा पर सीधा हमला होगा।

पार्टी नेताओं का कहना है कि उनके हस्तक्षेप का मकसद न सिर्फ़ सरकार को चुनौती देना है, बल्कि व्यापक राजनीतिक लामबंदी से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरना भी है।

एक शीर्ष कांग्रेस नेता ने कहा, सरकार दावा कर रही है कि वह सिर्फ़ नाम बदल रही है तथा कानून को सुव्यवस्थित कर रही है, लेकिन हक़ीक़त में वह ग्रामीण भारत की आत्मा पर हमला कर रही है। मनरेगा सबसे ग़रीब लोगों, सीमांत किसानों, खेत मज़दूरों और भूमिहीन परिवारों, के लिए काम की गरिमा और जीवन का सहारा है।

कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि यह मुद्दा ग्रामीण भारत में लोगों पर गहरा असर डाल सकता है, ख़ासकर ऐसे समय में जब महँगाई, बेरोज़गारी और कृषि संकट बड़ी चिंताएँ बनी हुई हैं। कांग्रेस कार्यसमिति विरोध प्रदर्शनों, रैलियों और राज्य इकाइयों के साथ तालमेल के लिए रोडमैप को अंतिम रुप देने वाली है और ऐसे में पार्टी मनरेगा को मोदी सरकार के ख़िलाफ़ अपने राजनीतिक आक्रमण का केन्द्रीय मुद्दा बना रही है।

जैसे-जैसे टकराव तेज़ हो रहा है, ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, जो कभी दोनों पार्टियों की सहमति वाला सोशल सेफ्टी नैट थी, अब सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ती राजनीतिक लड़ाई में टकराव का मुद्दा बन गई है।

'ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री बनने का कोई पैक्ट नहीं हुआ था'

कर्नाटक के मु.मंत्री सिद्धारमैया ने दो टूक कहा और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर। सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने रहने के अपने इरादे को स्पष्ट किया है, जबकि उनके उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की ओर से दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। शिव कुमार 2023 में हुए एक अघोषित समझौते पर कार्यकाल के बीच में नेतृत्व परिवर्तन की उम्मीदें लगाये हुये हैं। उस समझौते के अनुसार दोनों नेता राज्य के शीर्ष पद को "साझा" करेंगे तथा दोनों में से प्रत्येक इस पद पर ढाई वर्ष तक रहेगा।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने, राज्य में नेतृत्व संघर्ष के बीच, हाईकमान का समर्थन प्राप्त होने की बात कही, और अपने प्रतिद्वंदी डीके शिवकुमार के साथ ढाई साल मुख्यमंत्री की कुर्सी शेयर करने की किसी भी बात को दृढ़ता से नकार दिया है।

■ इसी बीच डी के शिवकुमार की अधीरता बढ़ती जा रही है, उन्हें उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान वादा निभाएगा और उन्हें मु.मंत्री की कुर्सी दी जाएगी।

■ डी के शिवकुमार ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हे व सिद्धारमैया को नेतृत्व के मसले पर चर्चा के लिए दिल्ली बुलाने की बात कही है और हम दोनों ही दिल्ली जाएंगे।

■ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का दावा है कि नेतृत्व के इस संघर्ष में उन्हें आलाकमान का पूर्ण समर्थन प्राप्त है।

शिवकुमार ने पार्टी हाई कमान से मिलने दिल्ली जाने के सम्बंध में कहा, "हम दोनों जाएंगे।"

शिवकुमार के इस बयान से एक दिन पहले सिद्धारमैया ने विधानसभा में जोर देते हुये कहा था कि वे अपने पद पर बने रहेंगे।

कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष के बीच, शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने दोनों नेताओं को यह बता दिया है कि इस मामले पर चर्चा करने के लिये उन्हें दिल्ली कब बुलाया जायेगा।

मीडिया ने शिवकुमार को यह कहते हुये उद्धृत किया, "मैं आपको सूचित करूंगा, मैं आपको सूचित किए बिना कुछ भी नहीं करूंगा। मैं आपसे छिपकर नहीं जाऊंगा," वे पत्रकारों के इन सवालों का जवाब दे रहे थे कि क्या वे और सिद्धारमैया पार्टी हाईकमान से मिलने के लिए नई दिल्ली जाएंगे। शिवकुमार ने कहा, "उन्होंने हम दोनों को कुछ बताया है, उन्होंने दोनों को फोन पर बताया है कि हमें कब बुलाया जाएगा। हम जाएंगे, हम दोनों ही जाएंगे।"

कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "हाईकमान ने कहा है कि वे दोनों को उचित समय पर बुलाएंगे, हम कॉल का इंतजार कर रहे हैं।"

विधानसभा में उत्तर कर्नाटक के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए, सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने कभी यह दावा नहीं कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल आधे समय तक सीमित होगा।

"मुझे पूरा विश्वास है कि हाईकमान मुझे पांच साल का कार्यकाल पूरा करने देगा," यह बात उन्होंने भाजपा के विधायकों के इस सवाल का जवाब देते हुए कही कि क्या सरकार द्वारा उत्तर कर्नाटक से किए गए वादे उनके कार्यकाल के दौरान पूरे हो जायेंगे।

गगनयान मिशन के लिए पैराशूट प्रणाली का ट्रायल सफल

इसरो ने इसे मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की दिशा में बड़ा कदम बताया

बेंगलुरु, 20 दिसंबर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर वापसी के दौरान उपयोग की जाने वाली एक प्रमुख सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण करके भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, गगनयान की दिशा में एक और कदम उठाया है।

इसरो की ओर से शनिवार को जारी बयान में बताया गया कि इसरो ने गुरुवार और शुक्रवार को चंडीगढ़ में एक उच्च गति परीक्षण सुविधा में विशेष पैराशूट (जिन्हें ड्रग पैराशूट के रूप में जाना जाता है) पर परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की। इन पैराशूटों को गगनयान क्रू मॉड्यूल को धीमा करने और स्थिर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इसरो के मुताबिक जब क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष से लौटता है, तो वह बेहद तेज़ गति से यात्रा करता है। सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के

■ इसरो ने कहा, यह पैराशूट प्रणाली गगनयान की पृथ्वी पर सफल वापसी सुनिश्चित करती है।

लिए पैराशूट का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले, छोटे पैराशूट इसके डिब्बे के सुरक्षात्मक आवरण को हटा देते हैं। इसके बाद दो ड्रग पैराशूट की तैनाती की जाती है, जो कैप्सूल को स्थिर करते हैं और उसकी गति को कम करते हैं। इसके बाद, मॉड्यूल को और धीमा करने के लिए बड़े पैराशूट छोड़े जाते हैं, जिससे यह सुरक्षित रूप से उतर सके। इसरो के अनुसार, सफल परिणाम ने गगनयान मिशन को वास्तविकता के एक कदम और करीब ला दिया है। गगनयान का लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908